भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3390
उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

पीएचडी हेतु सीटों की संख्या

†3390. **श्री सुधाकर सिंह:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सम्पूर्ण देश में पीएचडी की राज्य-वार कुल कितनी सीटें उपलब्ध हैं और क्या सरकार के पास पीएचडी छात्रों के नामांकन के संबंध में कोई आंकड़े हैं;
(ख) वर्तमान में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पर कितना व्यय हो रहा है और अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान पर हो रहे व्यय की तुलना में इसकी स्थिति क्या है;
(ग) सम्पूर्ण देश में पीएचडी के विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली औसत वृत्ति कितनी है और अमरीका, जर्मनी और चीन जैसे विकसित देशों में पीएचडी अध्येताओं को दी जाने वाले वृत्ति की तुलना में यह कितनी है; और
(घ) क्या सरकार की विशेषकर सामाजिक विज्ञान जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में पीएचडी सीटों की संख्या बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अध्येताओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में सुधार करने की कोई योजना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क)**:** अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई), 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार, पीएचडी में कुल नामांकन 2.33 लाख है। पीएचडी छात्रों का राज्यवार नामांकन https://www.education.gov.in/parl_ques उपलब्ध है।

(ख): वर्ष 2023-24 के लिए सामाजिक विज्ञान सहित अनुसंधान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी अनुदानों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	विवरण	2023-24 (रुपये लाख में)
1	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)	215.98
2	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान	5177.50
3	उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय और कॉलेज*	1659.16
4	अनुसंधान वैज्ञानिक	120.52
5	लघु एवं प्रमुख अनुसंधान परियोजना (विज्ञान एवं मानविकी)	114.18
6	कनिष्ठ और वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति	164420.47
7	महिलाओं हेतु पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	73.00
8	शिक्षकों को अनुसंधान पुरस्कार	25.85
9	शोध कार्यशालाएं, सेमिनार और सम्मेलन	0.00
10	सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए एमेरिटस फेलोशिप	246.85
	कुल	172053.51
	* अनुसंधान हेतु प्रयुक्त अनुदान का कुछ भाग।	

(ग) और (घ): यूजीसी उन एम. फिल / पीएचडी छात्रों को गैर-नेट फेलोशिप प्रदान करता है, जिन्होंने नेट उत्तीर्ण नहीं किया है और किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। पीएचडी छात्रों को नॉन-नेट फेलोशिप योजना के तहत 8000 रुपये प्रति माह का वजीफा मिलता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, यूजीसी द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने गैर-नेट फेलोशिप प्रदान करने के लिए लगभग 122.95 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया।

एआईएसएचई 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार, कुल पीएचडी नामांकन 2.33 लाख है, जो वर्ष 2021-22 में पीएचडी नामांकन 2.12 लाख से लगभग 10% अधिक है। कुल पीएचडी नामांकन वर्ष 2014-15 (1.17 लाख) से 2022-23 में लगभग दोगुना (2.33 लाख) हो गया है।

*****